भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

आर्थिक कार्य विभाग

लोक सभा

तारांकित प्रश्न सं. *233

(जिसका उत्तर सोमवार दिनांक 09 मार्च, 2026/18 फाल्गुन,1947 (शक) को दिया जाना है।)

वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों का प्रभाव

***233. श्री जिया उर रहमान:**

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या सरकार ने वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों के देश में मुद्रास्फीति पर पड़ने वाले प्रभाव की समीक्षा की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) सरकार द्वारा मुद्रास्फीति के दबाव को नियंत्रित करने के लिए उठाए जा रहे सुधारात्मक कदमों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या सरकार द्वारा आम उपभोक्ताओं को राहत प्रदान करने के लिए कोई राजकोषीय उपाय किए जाने का प्रस्ताव है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

वित्त मंत्री

(श्रीमती निर्मला सीतारामन)

(क) से (ग): विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

"देश में मुद्रास्फीति पर वैश्विक कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों का प्रभाव" पर श्री जिया उर रहमान द्वारा 09 मार्च, 2026 को पूछे जाने वाले लोकसभा तारांकित प्रश्न संख्या 233 के उत्तर में संदर्भित विवरण

(क): 28 फरवरी 2026 को पश्चिम एशिया में भू-राजनीतिक संघर्ष शुरू होने से पिछले एक वर्ष तक वैश्विक कच्चे तेल और भारतीय बास्केट दोनों की कीमत गिरावट की दिशा में रही है। फरवरी के अंतिम भाग और 2 मार्च 2026 तक के बीच, कच्चे तेल की एफओबी कीमत (भारतीय बास्केट) 69.01 डॉलर प्रति बैरल से बढ़कर 80.16 डॉलर प्रति बैरल हो गई। यह देखते हुए कि भारत की मुद्रास्फीति निचले स्तर के करीब है, इस बिंदु पर मुद्रास्फीति पर प्रभाव पर्याप्त होने का अनुमान नहीं है। अक्टूबर 2025 में जारी भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) की मौद्रिक नीति रिपोर्ट में यह अनुमान लगाया गया है कि यदि कच्चे तेल की कीमतें आधारभूत पूर्वानुमानों से 10 प्रतिशत अधिक हैं और यह मानते हुए कि घरेलू कीमतों पर पूरा प्रभाव पड़ेगा तो मुद्रास्फीति 30 बेसिस अंकों तक अधिक हो सकती है। हालांकि, मुद्रास्फीति पर वैश्विक कच्चे तेल की कीमत में वृद्धि का मध्यावधिक प्रभाव कई कारकों पर निर्भर करता है, जिसमें विनिमय दर उतार-चढ़ाव, वैश्विक मांग और आपूर्ति की स्थिति, मौद्रिक नीति संचरण, सामान्य मुद्रास्फीति की स्थिति और अप्रत्यक्ष तौर पर पास-थ्रू की सीमा शामिल है।

(ख) और **(ग):** उपभोक्ता मूल्य सूचकांक द्वारा मापी गई औसत खुदरा मुद्रास्फीति वर्ष 2023-24 में 5.4 प्रतिशत से घटकर वर्ष 2024-25 में 4.6 प्रतिशत और 2025-26 (अप्रैल-जनवरी) में 1.8 प्रतिशत हो गई। जनवरी 2026 में हेडलाइन मुद्रास्फीति 2.75 प्रतिशत थी और यह आरबीआई के 4%±2% के मुद्रास्फीति टॉलरेंस बैंड की निचली सीमा के आस-पास है। मुद्रास्फीति प्रबंधन के तौर पर, मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) ने फरवरी 2025 से नीतिगत दर में संचयी तौर पर 125 बेसिस अंकों की कमी की है। इसके साथ-साथ, सरकार ने मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने और आम नागरिक पर इसके प्रभाव को कम करने के लिए राजकोषीय और व्यापार नीति सहित कई प्रशासनिक उपाय भी किए हैं। इनमें *अन्य बातों के साथ-साथ* आवश्यक खाद्य वस्तुओं के लिए बफर स्टॉक में वृद्धि, क्रय किए गए अनाजों की खुले बाजार में योजनाबद्ध बिक्री, कम आपूर्ति की अवधि के दौरान आयात और निर्यात को नियंत्रित करने की सहूलियत, बाजार में चुनिंदा उत्पादों की अधिक आपूर्ति करने के लिए स्टॉक सीमा को लागू करना, भारत ब्रांड के तहत चुनिंदा खाद्य पदार्थों की रियायती दरों पर खुदरा बिक्री, खराब होने वाली बागवानी और कृषि उत्पादों के लिए बाजार हस्तक्षेप, ईंधन करों में कमी, वैज्ञानिक भंडारण क्षमता का निर्माण और सबसे महत्वपूर्ण, ₹12 लाख तक की वार्षिक आय (और वेतनभोगी व्यक्तियों के लिए मानक कटौती के साथ ₹12.75 लाख) को आय कर से छूट देकर व्यक्तियों के व्यय योग्य आय में वृद्धि और हाल ही में माल और सेवा कर (जीएसटी) दरों को युक्तिसंगत बनाना शामिल है।

****